मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराना

*43. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में 1995 के अन्त तक "मांग पर सभी को टेलीफोन उपलब्ध" कराने के संबंध में सरकार के आश्वासन को पूरा किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) और (ख) दिल्ली में 31.10.95 की स्थिति के अनुसार 1,17,743 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं। वर्ष 1995-96 के लिए 2,72,700 सीधी एकसचेंज लाइनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतः यह आशा की जाती है कि इस समय प्रतीक्षा सूची में दर्ज अधिसंख्य आवेदकों को मार्च 96 तक टेलीफोन प्रदान कर दिए जाएगें। तथापि, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में दिल्ली सहित सम्पूर्ण देश में 1997 तक मांग पर टेलीफोन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

श्री गोविन्दराम मिरी: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि 1995 के अंत तक दिल्ली में मांग पर सभी को टेलीफोन उपलब्ध कराए जायेंगे। किन्तु मुझे खेद है कि जैसा कि उनका नाम है, सुखराम वैसा उनका काम नहीं हुआ। ये बता रहे हैं कि 31.10.1995 तक 1,17,743 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं।....(**व्यवधान**)....मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 1994-95 का लक्ष्य क्या था और उसमें कितने की पूर्ति की गई है। (ब) मेरा प्रश्न है यह जो प्रतीक्षा-सूची 31.10.95 तक की है, यह तो अंतिम तिथि है लेकिन कब से है, यह भी बताने की कृपा करें? साथ ही प्रतीक्षा सूची जो बतायी गई है वह किस-किस श्रेणी की है, इसका विवरण दें और मांग के अनुसार पूर्ति का प्रतिशत क्या है?

श्री सुखराम: सभापति महोदय, मैंने अपने डिपार्टमेंट से कहा था कि यह एश्योरेंस मैंने पार्लियामेंट में दिया हुआ है कि 1995 में हम प्रतीक्षा-सूची को खत्म करेंगे। मगर फिर भी हम यह मानकर चलते हैं कि शायद जो यहां पर मेयर ने बात उठाई है, उसको भी अगर मानकर चलें तब भी हमारा जो लक्ष्य है इस साल का, वह 2,72,700 है और उसमें से 52 हजार हम दे चुके हैं और। लाख 17 हजार के लिए हमारी कोशिश है। कुछ एक्विपमेंट न मिलने की वजह से उसमें देरी तो हो गई, मगर मार्च के अंत तक अभी जो वेटिंग लिस्ट है, 1 लाख 17 हजार की, इसको देने की कोशिश करेंगे। नेशनल टेलीकाम पलिसी में हमने सारे देश से वायदा किया है कि 1997 में हम सारी प्रतीक्षा सूची को खत्म कर देंगे और उसमें दिल्ली भी शामिल है।

श्री गोविन्दराम मिरी: सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैंने अपना जो प्रश्न पूछा था वह यह था कि यह प्रतीक्षा सूची जो दी गई है वह कब से पेंडिंग है और किस किसी श्रेणी की है? उनका लक्ष्य क्या था और कितनों की पूर्ति की गई 95 तक। इसका पहले जवाब दें, फिर दूसरा सप्लीमेंटरी पूछूंगा।

श्री सुखराम : सभापति महोदय, जो वेटिंग लिस्ट है वह 31.10.95 तक की है।

श्री गोविन्दराम मिरी: कब से शुरू होती है?

श्री सुखराम : 31.10.95 तक की वेटिंग लिस्ट है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: इसकी शुरूआत कब से है?

श्री सुखराम : यह दो साल से ज्यादा की नहीं है। यह जो प्रतीक्षा सूची है यह दो साल से ज्यादा की नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Shri V.P. Duraisamy.

SHRI DIGVIJAY SINGH: He has to put his second supplementary, Sir.

MR. CHAIRMAN: I thought that he had put his second supplementary also.

श्री गोविन्दराम मिरी: मेरा सेकंड सप्लीमेंटरी।

माननीय मंत्री जी ने अभी जो कहा कि दो साल से पहले की नहीं है, मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अतारांकित प्रश्न संख्या 3183 का जो जवाब 24 अगस्त, 1995 को दिया गया था, उसमें उन्होंने कहा था कि: "Some of the persons who have booked their telephone connections during 1989 are still on the waiting list in the following States:

इसमें दिल्ली भी इन्क्लूड है, नं० 15 पर। अभी आपने कहा कि दो साल से ऊपर नहीं है। तो क्या 89 वालों की पूर्ति की गयी है? दूसरा मेरा प्रश्न है कि इसमें आपने बताया है कि अधिसंख्य आवेदकों को मार्च 96 तक टेलीफोन प्रदान कर दिए जाएंगे तो आपका क्या मतलब है? यह कितना प्रतिशत होगा क्योंकि आपने बड़ी-बड़ी होल्डिंग लगाई है आत्मप्रशंसा में। सरकार ने 100 में से 96 वायदे पूरे नहीं किए। क्या यह भी इसी

तरह से वायदा तोड़ने के लिए किया जा रहा है। 1996 तक लोगों को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? ग्राम पंचायतों को जो आपने टेलीफोन से जोड़ने का वायदा किया है, वह लक्ष्य भी पूरा होगा या नहीं होगा, यह बताने की कृपा करें?

श्री सुखराम: सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो 1989 की बात कही है, शायद यह दिल्ली की है या सारे देश की है, मैं इसको मालूम कर लूंगा। मगर जो मेरी सूचना है वह यह है कि यह वेटिंग लिस्ट बढ़ती जाती है। आज जो वेटिंग लिस्ट है वह 6 महीने के बाद और बढ़ेगी। जैसे दिल्ली में हमारी ई०आर०यू० यूनिट ने यह प्रोजेक्शन दिये हैं कि 1996 तक करीब 14 लाख से भी ज्यादा टेलीफोन की मांग होगी। दिल्ली में आज स्थिति ऐसी है कि हमारी जो सप्लाई है वह मांग से अधिक है। इस वास्ते जो आपने 1995 की बात की है, मैं नहीं कहता कि 1995 तक यह हो जाएगा क्योंकि दिल्ली में ऐसे भी कई क्षेत्र हैं जहां टेक्नीकल फीज़िबिलिटी न होने की वजह से ज्यादा टेलीफोन हम नहीं दे सकें मगर हमारी कोशिश होगी कि 1996 तक आज की जो प्रतीक्षा सूची है वह खत्म होगी। मगर जो आइंदा और बढ़ेगी, इसमें हम सप्लाई करेंगे।

SHRI V.P. DURAISAMY: Sir, I would like to know whether the Government assurance to provide telephone connections on demand in Tamil Nadu by the end of 1995 is going to be fulfilled. If so, when will it be fulfilled? If not, what are the reasons therefor?

SHRI SUKH RAM: Sir, I am not aware whether I made any commitment to liquidate the waiting list in Tamil Nadu by 1995. We had made this commitment to the whole nation and also in both the Houses of Parliament that by 1997 we will liquidate the entire waiting list in the entire country. But, as far as Tamil Nadu is concerned, I will find out whether I made some commitment and what actions are being taken in that regard.

श्रीमती वीणा वर्मा: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि अभी आपने जो कहा है कि वेटिंग लिस्ट को हम 1997 तक पूरा कर देंगे, यह हमारा वायदा है। इस वेटिंग लिस्ट को और जल्दी पूरा किये जाने के लिए मैं यह जानना चाहती हूं कि अब ऐसे बहुत से टेलीफोन है जो पहले टेलीफोन नहीं हैं बल्कि दूसरे, तीसरे या आठवें टेलीफोन कनेक्शन हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां या आर्गेनाइजेशंस है वह सिर्फ तीन हजार रुपये से जनरल केटेगरी में टेलीफोन की डिमांड करती है और 9-10 टेलीफोन ले लेती है। आपने अपनी टेलीकॉम पालिसी में यह मेंशन किया था कि आप एक ऐफिडेविट स्कीम लागू करेंगे। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि आप ऐफिडेविट भरवाएं जिसका पहला टेलीफोन है उसको तीन महीने के अन्दर दे दें जिससे कि आपकी यह जो वेटिंग लिस्ट है यह नीडवेस्ड और रियालिस्टिक बन सके और इसको आप जल्दी पूरा करा सकें। इसके लिए सरकार क्या सोच रही है? क्या आप ऐफिडेविट स्कीम लागू करने जा रहे हैं? मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि आप टेलीफोन आज कल ऑपटिक फाइबर बिछा कर दे रहे हैं जिसमें एक टेलीफोन की लागत लगभग 47 हजार रुपये का इनवेस्टमेंट आती है। महोदय, 40 प्रतिशत टेलीफोन ऐसे हैं जो कि सिर्फ रेंटल पर रहते हैं, बिल नहीं देना पड़ता है, फ्री कालज में टेलीफोन रहते हैं। अब कम्यूनिकेशन थ्रू स्काई की एक योजना है यू०एस० 80 (एस) वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल जिसमें सिर्फ ढाई मीटर का एंटेना लगा कर जगह-जगह थ्रू सेटेलाइट पी०सी० कंप्यूटर, वीडियो एंड प्लेयर आदि बहुत सी सुविधाएं दे सकते हैं। सिर्फ छोटा सा इनफ्रास्ट्रक्चर लगाना है जो बाहर की कंपनियों या विदेशों में बहुत प्रचलित है और जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उसे अपनाने जा रही है।

क्या इस सिस्टम पर भी सरकार विचार करने जा रही है कि देश में "वीसैट" को शुरू करेंगे जिससे टेलीफोन की मांग नीड वेस्ड हो सके और जल्दी इसको पूरा किया जा सके तथा इसको वायेबुल कास्ट इफेक्टिव बना सकें?

श्री सुख राम: सभापति जी, जहां तक वेटिंग लिस्ट का ताल्लुक है, हमको इस कन्टेक्स्ट में इसको देखना है कि 1991 की जो सेन्सस है उसमें 20 करोड़ ऐसे लोग हैं इस देश में जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा जो हमारी पंचवर्षीय योजना है उस योजना में 5,6,7 प्रतिशत जी०डी०पी० की ग्रोथ है फिर भी 20 करोड़ ही नहीं उसमें और एडीशन होती रही है। जब मैंने टेकओवर किया था तो उस समय 30 लाख की वेटिंग लिस्ट थी। 30 लाख की तो अब 50 लाख पर पहुंची है। मगर आज भी 25 लाख की वेटिंग लिस्ट है। इस वास्ते आज की जो वेटिंग लिस्ट है, किसी एक निर्धारित डेट की उसको तो हम खत्म कर देंगे। हम कह सकते है कि फलां तारीख तक खत्म कर देंगे। मगर वह बढ़ती जाती है। जब-जब भी लोगों को यह मालूम होता है कि टेलीफोन आन डिमांड

होने वाला है तो बहुत जल्दी लोगों की मांग उसमें बढ़ती जा रही है। इस वास्ते वेटिंग लिस्ट के लिए मैं यह नहीं कह सकता हूं कि वेटिंग लिस्ट किस डेट में खत्म हो जाएगी। जहां तक वीसैट का ताल्लुक है.....

श्रीमती वीणा वर्मा: जो अफीडेविट का मामला है।

श्री सुख राम: उसमें ओ०वाई०टी० की हमारी स्कीम है, नान ओ०वाई०टी० की हमारी स्कीम है। ओ०वाई०टी० में तकरीबन बहुत कम ऐसे लोग हैं। बम्बई जैसी सिटी में ओ०वाई०टी० में सैकड़ों में लोग होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। दिल्ली में भी सैकड़ों में होंगे ज्यादा नहीं हैं। दो तीन महीने में हम उसको खत्म कर देंगे। नान ओ०वाई०टी० भी हम खत्म कर रहे हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां करेंट हो गया है, आन डिमांड हो गया है। मगर जहां तक आपने वीसैट की बात कही है, वीसैट में हमने लाइसेंस दिए है प्राइवेट इंडिवीजुअल्स को। मुझे मुंह जबानी याद नहीं है, 6-7 लाइसेंस दिए हुए है। वे उनको शुरु करेंगे। लोगों को इससे फायदा होगा। इस तरह से मैं समझता हूं कि जहां तक टेलीफोन देने की बात है इसमें बहुत कमियां भी है, मैं मानता हूं इस बात को, मगर इन तीन चार वर्षों में बहुत बड़ा काम भी इस देश में हुआ है।

श्री राघवजी: सभापतिजी, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बताया कि पूरे देश में 25 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जो प्रतिक्षा सूची में हैं। जो अपेक्षा टेलीफोन विभाग से की गयी थी वह अपेक्षा पूर्ण नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन 25 लाख लोगों में से ऐसे उपभोक्ता कितने हैं जो दो वर्ष से अधिक प्रतीक्षा सूची में है और किस राज्य में यह संख्या सबसे अधिक है?

श्री सुख राम: सभापति जी, प्रश्न तो दिल्ली का है, मगर ...**(व्यवधान)**

श्री राघवजी: आपने अपने उत्तर में ही कहा है ...**(व्यवधान)**

श्री सुख राम: मैंने खुद ही कहा है। मैं इसका उत्तर दे रहा हूं आपको। आपने अगर मेरी बात को ठीक ढंग से सुना होगा तो मैंने कहा था कि 30 लाख उस टाइम पर थे जब मैंने टेकओवर किया था। वे तो लिकिवीडेट हो गए, उससे भी ज्यादा हो गये हैं, 50 लाख में हम पहुंचने वाले हैं और अभी जो सारे देश में है, वे 25 लाख है। ये तो बढ़ते हैं। मेरे पास यह आंकड़े तो नहीं है कि कितनी देरी में कोई वेटिंग लिस्ट में है और कहां-कहां है। आप उस पर सेपरेट नोटिस दीजिए तो उसका मैं आपको उत्तर दूंगा।

श्री सतीश अग्रवाल: ये नम्बर बढ़ रहे हैं इसमें आपको आपत्ति क्या है। आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं इंटेग्रेशन की बात करते है सारी वर्ल्ड इक्नामी से और टेलीफोन इतनी साधारण सुविधा है उसके बारे में चिंतित हो रहे हैं कि नम्बर बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है।

श्री सुख राम: मैं चिंतित नहीं हूं...**(व्यवधान)**

श्री सतीश अग्रवाल: मेरी बात सुनिए एक सेकिंड। एम०पी०ज का जो हमारा आउट आफ टर्न कोटा है 25 का उसका साल साल भर तक टेलीफोन नहीं लगता है। 94 के टेलिफोन्स, अब 94 का एंड आ गया है, लेकिन अभी तक टेलीफोन्स नहीं लगे हैं। टेलिफोन एडवायजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी एम०पीज० के साथ, उस में 30 डैज का नियम है, लेकिन एक-एक साल हो गया है इन एम०पीज० के रिकमंडेड केसेस को और बहुत से मैंबर्स हैं जिन के केसेस नहीं हुए हैं।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी: 6 महीने हो गए है।

मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी: 6 महीने हो गए हैं।

श्री सतीश अग्रवाल: सर, आप इस में प्रोटेक्शन दीजिए । 30 डेज की लिमिट है।

Kindly direct the Minister to see to it that at least the out-of-turn allotment of telephones recommended by the Members of Parliament should be cleared within the prescribed period of thirty days. But even after the expiry of one year, they have not been installed.

तो एक्सपायरी ऑफ वन इयर में भी टेलिफोन इंस्टाल नहीं हुए हैं और पैसे मांगते है आप के डिपार्मेंट के लोग। कहते है पैसा दो ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Allow the Minister to answer.

श्री राघवजी: सभापति जी, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कितने समय से लोग प्रतीक्षा सूची में हैं...**(व्यवधान)**.....तीन-तीन साल से लोग प्रतीक्षा सूची में है और उन को टेलफोन नहीं मिला है...**(व्यवधान)**.....

श्री सुख राम: अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं आप की आपत्ति का उत्तर दूंगा। सभापति जी, जैसेकि माननीय सदस्यों ने कहा कि एक-एक साल तक उन के केसेज नहीं हुए यह बड़े अफसोस की बात है। अगर आप लिखकर दें कि किस-किस का है तो मैं उस के मुताबिक एक्शन लूंगा, जहां यह देरी हुई है। मगर हमारे निर्देश है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो आउट ऑफ टर्न अलाटमेंट्स है वह 30 डेज के अंदर होना चाहिए।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी: नहीं हो रहा है ...(**व्यवधान**).....

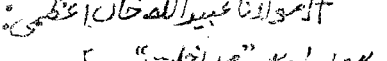

श्री सतीश अग्रवाल: कोई भी मेंबर खड़ा होकर कह दे कि 30 डेज में इंस्टाल हुआ हो? एक का भी नहीं हुआ है।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी: पैसा मांगते है...(**व्यवधान**).....

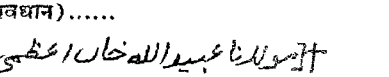

श्री मोहम्मद सलीम: अपार्ट फ्राम डिले, अगर नागपुर के लिए रिकमेंडेशन होता है तो वह मध्य प्रदेश के लिए भेज देते है।

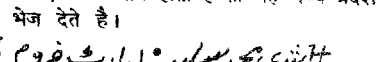

श्री सतीश अग्रवाल: आप एक कमेटी बना दीजिए इस की जांच के लिए।

श्री सुख राम: मैंने यह कहा है कि इस की बाकायदा मंथली और 3 महीने में हम रिव्यू करते है। उस में कुछ केसेस में ऐसा पाया गया है कि जिन्होंने अपने केसेस रिकमेंड किए, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया या कहीं-कहीं एड्रेसेस में कमी थी। Please listen to what I am going to say.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: It is provided in the rules that those cases which have been recommended by the MPs should be decided within thirty days. We send the photo copies of the registration.

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी: सर, रजिस्ट्रेशन की कॉपी लगाकर भेजी जाती है और ऐसा भी होता है कि अगर दो-एक आदमी का भी हो गया है तो बगैर पैसा लिए नहीं करते। बगैर पैसा दिए टेलिफोन नहीं लगाते। खुलमखुल्ला पैसा चल रहा है आप के विभाग में ...(**व्यवधान**)...

श्री सुख राम: मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि अभी मैं सारी सूची देखकर जहां-जहां डिले हुई है, अगर किसी अधिकारी/कर्मचारी की वजह से डिले हुए है उन के ऊपर एक्शन भी लूंगा और यह एंश्योर करूंगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो आउट ऑफ कर्न कोटा है, वह जल्दी होना चाहिए

श्री दिग्विजय सिंह: यह हम आज पहली बार नहीं उठा रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN : Q.No. 24. Shri Virendra Kataria. *(Interruptions)* The Minister said that he will look into it. *(Interruptions)* I have gone to the next question. You have taken a lot of time for this question. *(Interruptions)*

SHRI CHATURANAN MISHRA: Sir, the action taken should be reported to the House.

US views about Pak Terrorism

*44. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item captioned "Wisner not for Pak as terrorist State" which appeared in the 'Hindustan Times', dated the 21st August, 1995;

(b) if so, what is the reaction of Government thereon;

(c) whether the recent release of the U.S. State Department's own Annual Report on Pattern of Global Terrorism indicates Pak's involvement in terrorist activities; and

(d) the steps being taken by Government to reconcile with these two contradicitory statements of the U.S. Government?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) Yes sir.

(b) The news item refers to the reluctance of the US to declare Pakistan a terrorist State for want of proof and specific findings. Government do not share the view of the US, which the US Ambassador has reitereated in the press conference, that there was no proof of Pakistan Govenrment's involvement in terrorist activities in India. On the contrary, the available evidence, both within India and within the US system, clearly establishes that Pakistan is actively engaged in financing, abetting, training and arming of militants and infiltration into India, particularly J&K.

Transliteration in Arabic Script.